भारतीय शहरी क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन: विश्व बैंक रिपोर्ट

प्रस्तावना

- भारत में शहरीकरण (Urbanization) की गति तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से निपटने की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। हाल ही में, विश्व बैंक (World Bank) और भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक रिपोर्ट ने भारतीय शहरों के लिए गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहरों को 2050 तक जलवायु-लचीला (climate-resilient) बुनियादी ढाँचा (infrastructure) और सेवाएँ स्थापित करने के लिए 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

विश्व बैंक की रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट, "Towards Resilient and Prosperous Cities in India," में यह भविष्यवाणी की गई है कि भारत की शहरी जनसंख्या 2050 तक 951 मिलियन तक पहुँच जाएगी, और 2030 तक, भारतीय शहरों में 70% नई नौकरियाँ (jobs) उत्पन्न होंगी। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय शहरों को दो प्रमुख संकटों का सामना करना पड़ेगा: बाढ़ (flooding) और अत्यधिक गर्मी (extreme heat)।

शहरी स्वायत्तता और जलवायु परिवर्तन

- विश्व बैंक के भारत के लिए देश निदेशक, अगस्ते तानो कूआमे (Auguste Tano Kouame) का मानना है कि शहरी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) के लिए प्रभावी ढंग से निवेश करने के लिए कुछ स्वायत्तता (autonomy) की आवश्यकता है। उनका कहना है कि जब शहरों को निर्णय लेने और उसे लागू करने का अधिकार दिया जाता है, तो वे बेहतर तरीके से काम करते हैं और संसाधनों को बेहतर तरीके से जुटा पाते हैं।

74वीं संवैधानिक संशोधन (74th Constitutional Amendment Act)

- 74वीं संविधान संशोधन (74th Constitutional Amendment Act) 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। हालांकि, कई राज्यों में अभी भी इस संशोधन को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि कुछ रूप में इस संशोधन को लागू किया जाए ताकि शहरों को अपनी जलवायु लचीला योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की स्वतंत्रता मिल सके।

बाढ़ और अत्यधिक गर्मी से खतरा

- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहरों में बाढ़ और अत्यधिक गर्मी का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्लुवियल बाढ़ (Pluvial Flooding) के कारण हर साल 2030 तक भारतीय शहरों को 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो 2070 तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में "हॉट आइलैंड प्रभाव" (Urban Heat Island Effect) भी बढ़ रहा है, जिसके कारण शहरों में रात के समय तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है।

मृत्यु दर में वृद्धि

- अत्यधिक गर्मी के कारण मौतों की संख्या 2050 तक 3 लाख प्रति वर्ष तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि कुछ उपाय जैसे कार्य समय को सुबह और शाम के समय में स्थानांतरित करना, शहरी हरियाली (urban greening), और ठंडे छत (cool roofs) लगाना आदि अपनाए जाएं, तो 1.3 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं।

वित्तीय निवेश और निजी क्षेत्र की भूमिका

- रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में निजी क्षेत्र की भागीदारी (private sector participation) बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को एक वित्तीय रोडमैप (financial roadmap) तैयार करना चाहिए ताकि जलवायु-लचीला योजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाया जा सके।

निष्कर्ष और सिफारिशें

- रिपोर्ट में कई सिफारिशें दी गई हैं, जिनमें जोखिम मूल्यांकन (risk evaluation), पूंजी जुटाना (capital mobilization), और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मानक स्थापित करना शामिल है। शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने और उनका सामना करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, और इसके लिए उन्हें स्वायत्तता (autonomy) और संसाधनों की आवश्यकता है।

- भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए यह रिपोर्ट एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल सरकारी योजनाएँ ही पर्याप्त नहीं होंगी। शहरों को अधिक स्वतंत्रता और शक्ति देने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूँढ सकें और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सकें।